नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Saturday 10th January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 255 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

रेल मुसाफिरों को 3% की राहत! भोपाल मंडल 14 जनवरी से लागू करेगा 'रेलवन ऐप' पर डिस्काउंट स्कीम

भोपाल: रेलवे स्टेशन की खिड़कियों पर जनरल टिकट के लिए लगने वाली लंबी कतारों और चिल्लर (सिक्कों) की किचकिच से अब आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम मुसाफिरों की आर्थिक बचत का भी रास्ता साफ कर दिया है। आगामी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर्व के मौके पर 'रेलवन मोबाइल ऐप' के जरिए अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में 3 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।

जेब पर कम पड़ेगा बोझ, सफर होगा सुहाना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के अनुसार, यह योजना उन मध्यमवर्गीय और दिहाड़ी पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी जिनके लिए एक-एक रुपया कीमती है। अभी तक ऐप के 'वॉलेट' से टिकट बुक करने पर कैशबैक मिलता था, लेकिन अब किसी भी डिजिटल माध्यम (UPI, डेबिट कार्ड आदि) से भुगतान करने पर सीधे पैसे कम कटेंगे। यह सुविधा फिलहाल छह महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है।

ठंड में लाइन में लगने के बजाए मोबाइल से बुकिंग

भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने 'navbharattimes.com' को बताया कि यात्रियों को सम्मानजनक और सुगम यात्रा का अनुभव देना है। कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर लाइन में लगने के बजाय, यात्री अब अपने मोबाइल से घर बैठे या स्टेशन के पास से ही रियायती दरों पर टिकट ले सकेंगे। 14 जुलाई 2026 तक चलने वाली इस योजना के परिणामों के आधार पर इसे स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।

चीन पर रहम, भारत पर सितम... टैरिफ को लेकर अमेरिका का रवैया अलग-अलग क्यों?

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर एक बिल पर सहमति जताई है। इस बिल के अनुसार अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक टैरिफ लगा सकता है। इसमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। माना जा रहा है कि अगर 500 टैरिफ लगता है तो भारत के लिए अमेरिका को चीजें एक्सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।

इस बिल के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चीन को इससे राहत दे सकता है। अमेरिका चीन के साथ ऐसा पहले भी कर चुका है। दरअसल, अमेरिका का भारत और चीन के प्रति रवैया बिल्कुल अलग है। अमेरिका चीन के प्रति नरमी बरत रहा है, जबकि भारत पर सख्ती दिखा रहा है।

चीन पर नरम क्यों है अमेरिका?

अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव भी देखने को मिलता रहता है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन चीन के साथ सावधानी से पेश आ रहा है। इसका एक बड़ा कारण चीन का दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (rare earth minerals) पर दबदबा है।

ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए बहुत जरूरी हैं।

भले ही चीन रूस तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन उस पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया गया है। ट्रंप ने पिछले साल 12 अगस्त को चीनी आयात पर नए शुल्क स्थगित कर दिए थे। उन्होंने टैरिफ को 30% पर बनाए रखा, जो भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ से काफी कम है।

चीन दिखा चुका है अपना रंग

चीन ने भी अमेरिका के प्रति सख्त रवैया अपनाया है। चीन ने अमेरिका को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और चुम्बकों के निर्यात पर लाइसेंस प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे अमेरिकी उद्योगों, खासकर ऑटो निर्माताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों में हड़कंप मच गया था। ये क्षेत्र चीनी आपूर्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। आपूर्ति में थोड़ी सी भी रुकावट उत्पादन में देरी और सप्लाई चेन में गड़बड़ पैदा कर सकती है।

घरेलू निर्माताओं के दबाव में अमेरिका को बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को लेकर हुए इस गतिरोध ने दिखाया कि चीन किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।

इसलिए चीन के खिलाफ सख्त टैरिफ रणनीति अपनाना अमेरिका के लिए एक जोखिम भरा कदम है। भारत पर ट्रंप की सख्ती क्यों?

चीन के विपरीत अमेरिका भारत पर सख्ती अपनाता रहा है। दरअसल, भारत के पास चीन जैसी रणनीतिक ताकत नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। लेकिन, भारत के पास चीन जैसी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन पर नियंत्रण की शक्ति नहीं है। ट्रंप ने बार-बार भारत की व्यापार नीतियों पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने भारत पर अमेरिकी सामानों पर ऊंचे टैरिफ और बाधाएं लगाने का आरोप लगाया है।

भारत पर कुल 50% टैरिफ इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि भारत रूस से काफी मात्रा में तेल खरीद रहा है। अमेरिका का मानना है कि इससे यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो अमेरिका टैरिफ और बढ़ा सकता है। उन्होंने इस दबाव को सीधे तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध से जोड़ा। यह टैरिफ बढ़कर 500 फीसदी तक हो सकता है।

WPL 2026: आखिरी ओवर ड्रामा में RCB ने मुंबई इंडियंस को हराया — 5 खिलाड़ी जिन्होंने मैच में 'विलेन' के रूप में दिखाया खराब प्रदर्शन

NEWS AGENCY

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के सीज़न के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस को बेहद रोमांचक अंदाज़ में हराया। मैच अंतिम ओवर तक खतरनाक मोड़ पर था और 20वें ओवर की अंतिम गेंद तक जीत का फैसला टिका हुआ था।

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए संतुलित प्रदर्शन किया और 154/6 का स्कोर बनाया, लेकिन RCB ने लक्ष्य का पीछा कम नहीं होने दिया। आखिरी ओवर में RCB को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे, और नादिन डी क्लार्क ने चौकों और छक्कों की मदद से टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाई।

इस मैच में कई अनुभवी खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। नैट साइवर-ब्रंट, जिन्हें मैच में बड़ा योगदान देने की उम्मीद थी, सिर्फ 4 रन पर आउट हो गईं और गेंदबाज़ी में भी उनके ओवर ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में टीम को आगे नहीं बढ़ा सकीं और मात्र 20 रन ही बना पाईं।

इसके अलावा अमेलिया केर का बल्ला भी खामोश रहा और शबनम इस्माइल तथा साइका इशाक ने गेंदबाज़ी में काफी रन लुटा दिए, जिससे RCB को अंतिम ओवर में उछाल मिला। इस तरह WPL 2026 के पहले शानदार मुकाबले में RCB ने आखिरी ओवर के नाटकीय मोड़ का पूरा फायदा उठाया और जीत अपने नाम की, जबकि मुंबई इंडियंस के कुछ खिलाड़ी 'विलेन' बनते नजर आएं।

ऑटोमैटिक ब्रेकिंग से लेकर कैशलेस इलाज तक: भारत में V2V तकनीक लागू, सड़क सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव

नई दिल्ली। भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन तकनीक को देश में 2026 के अंत तक लागू किया जाएगा। इससे वाहन आपस में सीधे संवाद कर सकेंगे और संभावित खतरों से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट भेज सकेंगे।

V2V तकनीक का उद्देश्य वाहनों को सीधे और रियल-टाइम में संदेश आदान-प्रदान करने की क्षमता देना है। जब एक वाहन अचानक ब्रेक लगाएगा, या कोई वाहन सड़क पर खड़ा रहेगा, तो आसपास के वाहनों को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। इससे रीयर-एंड टक्कर और कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थितियों में दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना बढ़ जाएगी।

सरकार की योजना के तहत यह तकनीक पहले नई गाड़ियों में अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी और बाद में पुराने वाहनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। दूरसंचार विभाग ने V2V के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम को भी स्वीकृत कर दिया है, जिससे यह प्रणाली निर्बाध रूप से काम कर सकेगी।

इस पहल के साथ ही सरकार कैशलेस इलाज योजना भी शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में बिना अग्रिम भुगतान के इलाज की सुविधा मिलेगी और गंभीर मामलों में 1.5 लाख रुपये तक का खर्च कवर होगा। साथ ही, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों को 'राहवीर' के रूप में पुरस्कार भी दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि V2V तकनीक, जब सड़क पर विविध सुरक्षा प्रणालियों जैसे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ मिलकर काम करेगी, तो यह दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह कदम भारत में सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने और यात्रियों तथा वाहन चालकों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

पाक रक्षा मंत्री का विवादित बयान: अमेरिका से नेतन्याहू के 'अपहरण' की मांग

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बेहद विवादित और तीखा बयान दिया है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि यदि अमेरिका वास्तव में इंसानियत में विश्वास करता है, तो उसे नेतन्याहू को उसी तरह 'किडनैप' कर लेना चाहिए, जैसे हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था।

ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि तुर्की यदि नेतन्याहू को पकड़ने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान उसका पूरा समर्थन करेगा। उन्होंने नेतन्याहू को "मानवता का सबसे बड़ा अपराधी" करार देते हुए आरोप लगाया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, उनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती।

आसिफ ने दावा किया कि पिछले चार से पांच हजार वर्षों में किसी भी समुदाय ने वैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा इजरायल ने फिलिस्तीनियों के साथ किया है। उन्होंने नेतन्याहू के समर्थकों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि कानून ऐसे अपराधियों का साथ देने वालों के बारे में क्या कहता है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के गिरफ्तारी वारंट का हवाला देते हुए कहा कि नवंबर 2024 में नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, इजरायल ने इन आरोपों और वारंटों को सिरे से खारिज किया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया था, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है।

दिल्ली: सिख गुरु अपमान विवाद पर MCD सदन में हंगामा, भाजपा-आप में तीखी झड़प

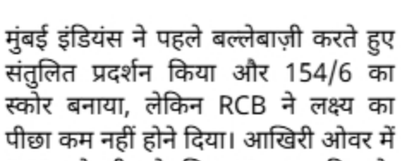

नई दिल्ली। सिख धर्मगुरुओं के कथित अपमान को लेकर MCD सदन में जमकर हंगामा हुआ और बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस विवाद की शुरुआत आप पार्षदों द्वारा विरोध से हुई, जिन्होंने महापौर कार्यालय का गेट तोड़ने का प्रयास भी किया। भाजपा और AAP पार्षदों के बीच शब्दों की जंग के बाद सभापति को कार्यवाही रोकनी पड़ी क्योंकि सदन में आदेश बहाल रखना मुश्किल हो गया। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि AAP नेताओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक शोरगुल के लिए बनाया गया है। घटना से MCD की कार्यवाही प्रभावित हुई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी।

नाशिक में संयुक्त रैली: उद्धव–राज ने भाजपा के 'चुनावी हिंदुत्व' पर तीखी कटाक्ष, भ्रष्टाचार और वादों पर सवाल

NEWS AGENCY

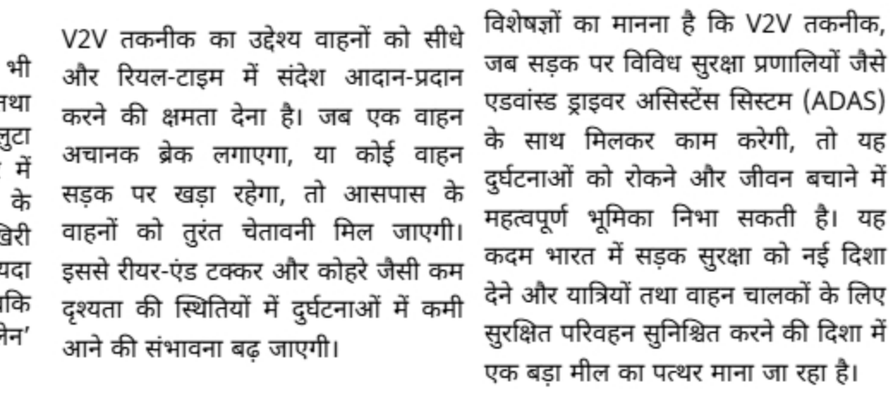

नाशिक से — उद्धव ठाकरे ने नाशिक में आयोजित भाजपा के खिलाफ रैली में भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व के नाम पर पाखंड और चुनावी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व "सच्चा हिंदुत्व" नहीं बल्कि सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार है। ठाकरे ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर भाजपा का हिंदुत्व वास्तविक होता तो वह नाशिक के तपोवन जैसे पवित्र स्थान से पेड़ों को नहीं काटती और बिल्डरों को ज़मीन नहीं देती। उन्होंने पार्टी पर भ्रष्ट और अनुचित हस्तियों को शामिल करने के आरोप भी लगाए।

ठाकरे ने भाजपा की एमआईएम के साथ गठबंधन और कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन की तुलना करते हुए भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि भाजपा के फलक पर दिखने वाला "हिरवा रंग" (हिंदुत्व का प्रतीक) अब खोखला हो गया है और प्रत्यक्ष में उसने सत्ता के लिए किसी भी कदम से परहेज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगामी महानगरपालिका चुनाव केवल हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं बल्कि सुशासन, विकास और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित होना चाहिए। ठाकरे ने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि उनकी यूनिटी लाइन (जैसे शिवसेना-मनसे गठबंधन) असली हिंदुत्व और राष्ट्रीयता को दर्शाती है। रैली में राज ठाकरे ने भी भाजपा द्वारा नेताओं को 'इम्पोर्ट' और बिना मुकाबले के उम्मीदवारों की समस्या पर तीखी टिप्पणी की। दोनों ने मिलकर भाजपा पर विकास की परियोजनाओं को पूरा न करने और सत्ता की भूख को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

भाजपा सरकार की नजरों में 'अब्दुल' का काम सिर्फ... ये क्या बोल गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, छिड़ेगा सियासी घमासान

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर समाज को बीमार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नजरों में 'अब्दुल' का काम सिर्फ पंक्चर लगाना होना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि 50 मुस्लिम छात्रों के मेडिकल एंट्रेंस पास करने पर भाजपा ने मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसी बातें कह दी है जो कि सियासी तूफान ला सकता है। उन्होंने अपने बयान में बिना नाम लिए मुस्लिम समुदाय को लेकर बात की है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बीमार करने का आरोप लगाया है।

क्या कहा पवन खेड़ा ने?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार की नजरों में 'अब्दुल' का काम सिर्फ पंक्चर लगाना होना चाहिए। इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि 50 मुसलमान बच्चे अपनी काबिलियत से मेडिकल एंट्रेंस पास कर गए। इसीलिए मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया। पहले तो पूरे देश को यह समझाया गया कि 'अब्दुल' का इलाज करना ज़रूरी है, और फिर 'अब्दुल' के इलाज के चक्कर में देश को, समाज को बीमार कर दिया।

छिड़ सकता है सियासी घमासान

बता दें कि पवन खेड़ अक्सर भाजपा के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं। इस बार के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पवन खेड़ा के बयान पर प्रतिक्रिया देती है।

पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर अरेस्ट भी हो चुके हैं पवन खेड़ा

कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को गौतम अदाणी के पिता से जोड़कर जानबूझकर उपहास करने की नीयत से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई थी। हजरतगंज कोतवाली पहुंचे भाजपा नेताओं ने पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ कई जगहों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

बेलगाम टैरिफ और वैश्विक दबाव : ट्रंप की चेतावनी, भारत की संप्रभुता और नई चुनौती

संपादकीय... |

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मंच पर एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया है—क्या आर्थिक ताकत के दम पर किसी संप्रभु राष्ट्र की नीतियों को बदला जा सकता है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने की नई चेतावनी ने भारत-अमेरिका संबंधों में छिपे तनाव को सतह पर ला दिया है। 9 जनवरी 2026 तक उपलब्ध बयानों और रिपोर्टों के अनुसार, यह विवाद अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ चुका है।

टैरिफ चेतावनी का असली संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters और भारतीय समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप की नाराज़गी का प्रमुख कारण भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की निरंतर खरीद है। अमेरिका का तर्क है कि इससे रूस को आर्थिक संबल मिलता है, जबकि भारत का रुख स्पष्ट है—ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आंतरिक प्राथमिकता होती है। भारत सरकार ने कई बार कहा है कि तेल खरीद का फैसला वैश्विक बाजार दरों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, न कि किसी भू-राजनीतिक दबाव में।

ट्रंप द्वारा यह कहना कि भारत “अमेरिकी नीति के अनुरूप नहीं चला” और इसलिए टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं, दरअसल उस संरक्षणवादी सोच को दर्शाता है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बार-बार अपनाई थी।

अमेरिकी टैरिफ नीति : दबाव का औजार

2025 में अमेरिका द्वारा कार्यकारी आदेश के ज़रिये भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत तक कर दिया गया। Reuters के अनुसार, अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा विधेयक भी चर्चा में है, जो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। यह प्रस्ताव वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह WTO की भावना के विपरीत एकतरफा आर्थिक दंड को वैध ठहराने की कोशिश करता है।

भारत का आधिकारिक रुख : दबाव में न झुकने की नीति

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर असाधारण स्पष्टता दिखाई है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ताओं और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के माध्यम से जारी बयानों में कहा गया है कि भारत किसी भी देश के दबाव में अपनी ऊर्जा या व्यापार नीति नहीं बदलेगा। भारत का मत है कि जब यूरोप और अन्य देश भी रूस से ऊर्जा आयात कर रहे हैं, तो केवल भारत को निशाना बनाना न तो न्यायसंगत है और न ही संतुलित।

यह रुख केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक कूटनीतिक सोच का प्रतिबिंब है—रणनीतिक स्वायत्तता।

आर्थिक असर : आंकड़ों के पीछे की सच्चाई

PTI और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 129 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 87 अरब डॉलर था। वस्त्र, फार्मा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग वस्तुएँ इस व्यापार की रीढ़ हैं।

यदि टैरिफ और बढ़ते हैं, तो इसका सीधा असर छोटे और मध्यम निर्यातकों पर पड़ेगा। रोजगार-प्रधान क्षेत्रों में उत्पादन घटने और लागत बढ़ने का खतरा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक ऐसा दबाव बना रहा तो भारत की विकास दर पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया : भीतर की बहस

देश के भीतर भी इस मुद्दे पर बहस तेज हुई है। विपक्षी दलों ने ट्रंप की चेतावनी को भारत की संप्रभुता पर आघात बताया है। वहीं सरकार का रुख यह है कि कूटनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। यह बहस लोकतंत्र की मजबूती को भी दर्शाती है—जहां बाहरी दबाव पर भीतर मंथन होता है।

भारत की रणनीति : विकल्पों की तलाश

सरकार ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और निर्यात बाजारों के विविधीकरण पर जोर इसी रणनीति का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर भारत वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

साथ ही, WTO और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत अपने पक्ष को मजबूती से रखने की तैयारी में है। यह संकेत है कि भारत टकराव नहीं, बल्कि नियम-आधारित समाधान चाहता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

ट्रंप की टैरिफ नीति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। चीन, यूरोप और लैटिन अमेरिका भी इसी संरक्षणवादी दृष्टिकोण का सामना कर चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी नीतियाँ अल्पकाल में घरेलू राजनीति को साध सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं।

समाप्ति विचार

9 जनवरी 2026 तक की स्थिति स्पष्ट है—भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद केवल व्यापारिक खींचतान नहीं, बल्कि यह सवाल है कि 21वीं सदी में वैश्विक संबंध किस दिशा में जाएंगे। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह दबाव की राजनीति से नहीं, बल्कि संतुलित कूटनीति और राष्ट्रीय हित से अपने फैसले लेगा।

ट्रंप की चेतावनियाँ भले ही सुर्खियाँ बनें, लेकिन भारत के लिए असली परीक्षा अपनी आर्थिक मजबूती, रणनीतिक धैर्य और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास बनाए रखने की है। यही इस पूरे विवाद का केन्द्रीय संदेश है।

WORLD NEWS | वेनेजुएला के पास पकड़े गए तेल टैंकर पर सवार रूसी नागरिकों को छोड़ेगा अमेरिका

वेनेजुएला के पास पकड़े गए तेल टैंकर पर सवार रूसी नागरिकों को छोड़ेगा अमेरिका, तीन भारतीयों का क्या होगा

मॉस्को: अमेरिका ने वेनेजुएला के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर मे जब्त तेल टैंकर के चालक दल में शामिल रूसी नागरिकों को छोड़ने का ऐलान किया है। रूस ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। इस टैंकर पर दो रूसी नागरिक सवार हैं। वहीं, टैंकर के चालक दल में तीन भारतीय भी शामिल है, जिनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस टैंकर पर 20 यूक्रेनी और छह जॉर्जियाई नागरिक भी सवार हैं। हालांकि, अमेरिका ने उनकी रिहाई को लेकर कुछ नही कहा है।

रूसी टैंकर के चालक दल में किन देशों के नागरिक

उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी ध्वज वाले टैंकर मेरिनेरा (जिसे पहले बेला-1 के नाम से जाना जाता था) को बुधवार को जब्त कर लिया था। इस पर 17 यूक्रेनी नागरिक, छह जॉर्जियाई नागरिक, तीन भारतीय नागरिक और दो रूसी नागरिक सवार थे।'' पहले अमेरिका ने कहा था कि इस टैंकर के चालक दल को हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की योजना है।

रूस ने अमेरिका के फैसले पर क्या कहा

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक बयान में कहा, ''हमारे अनुरोध के जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक में एक अभियान के दौरान अमेरिका द्वारा जब्त किये गए टैंकर मेरिनेरा के चालक दल के दो रूसी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया है।'' मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में जखारोवा ने कहा, ''हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।''

रूस ने अपने नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया

बयान में कहा गया, ''हम अपने देशवासियों की शीघ्र वतन वापसी सुनिश्चित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल और व्यावहारिक कार्य शुरू कर रहे हैं।'' हालांकि, इसमें टैंकर पर सवार चालक दल के अन्य सदस्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

रूसी विदेश मंत्रालय की यह घोषणा मॉस्को द्वारा वाशिंगटन से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील करने और उसकी 'नव-उपनिवेशवादी' प्रवृत्तियों को दृढ़ता से खारिज करने के एक दिन बाद आई है।

चालक दल के खिलाफ केस चलाएगा अमेरिका

व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास) ने टैंकर को जब्त किए जाने के बाद घोषणा की थी कि चालक दल के सदस्यों को अमेरिका की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी सेना ने बेला-1 को जब्त कर लिया और बाद में इसका नियंत्रण कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दिया। ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्ला से जुड़ी एक कंपनी के लिए माल की तस्करी करने के आरोप में इस जहाज पर 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था।

WORLD NEWS | पाकिस्तान को खा रही 'डच डिजीज', भारत पैदा कर रहा कंप्यूटर सांइटिस्ट

Pakistan Economy Vs India: पाकिस्तान को खा रही 'डच डिजीज', भारत पैदा कर रहा कंप्यूटर सांइटिस्ट...किसने खोली पोल

● Reporter Name

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व गवर्नर रह चुके इशरत हुसैन वेबसाइट डॉन के लिए एक लेख लिखा है-विदेश से भेजे हुए पैसे: वरदान या अभिशाप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरअसल, पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है। इशरत ने इसमें पाकिस्तान की कंगाली को उजागर करते हुए भारत की तारीफ की है। वहीं, भारत हाल ही में जापान को पछाड़कर अमेरिका, रूस और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गया है। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं, भारत का लक्ष्य जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जबकि, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप-10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी 410 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 42वें नंबर पर है।

डच डिजीज क्या है

इशरत हुसैन ने कहा है कि अक्सर अर्थव्यवस्था में मजदूरों द्वारा भेजे गए पैसे की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंता जताई जाती हैं। ये चिंताएं आमतौर पर ब्रेन ड्रेन, ज्यादा खपत, इंपोर्ट लीकेज, एक्सचेंज-रेट ओवरवैल्यूएशन और डच डिजीज की संभावना जैसे कथित जोखिमों पर केंद्रित होती हैं। आमतौर पर डच डिजीज अर्थव्यवस्था की एक शब्दावली है। जिसका मतलब है किसी एक सेक्टर का तेजी से बढ़ना और बाकी दूसरे सेक्टरों में गिरावट के साथ ठहराव आना। पाकिस्तान में यही हो रहा है।

विदेशों से आए पैसे होते हैं लाइफलाइन

द डॉन के अनुसार, कामगारों के भेजे ये पैसे सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं। बाहरी आमदनी का एक स्थिर सोर्स होने के नाते ये विदेशी मुद्रा भंडार बनाने, बाहरी कर्ज़ पर निर्भरता कम करने, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने और चालू खाते पर दबाव कम करके मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये गरीबी कम करने, आय असमानताओं को कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए फाइनेंसिंग करके मानव पूंजी को मजबूत करते हैं। आर्थिक संकट के समय ये परिवारों के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं।

ब्रेन गेन इफेक्ट होता है, भारत को प्रोत्साहन

इशरत हुसैन बताते हैं कि पाकिस्तान में माइग्रेट करने की तैयारी कर रहे लोगों और वापस लौटने वालों में स्किल अपग्रेडिंग के भी सबूत मिले हैं, जिससे ब्रेन गेन इफेक्ट होता है। स्टडीज़ से पता चलता है कि विदेशों में नौकरी के अवसरों ने फिलीपींस को ज्यादा नर्सों को ट्रेन करने और भारत को ज्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे असल में देश में स्किल्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ी है।

रेमिटेंस के बारे में क्यों गलतफहमी

रेमिटेंस के बारे में गलतफहमियां ज्यादातर इस बात से पैदा होती हैं कि WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज और IMF के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BOP) फ्रेमवर्क के तहत वर्कर्स के रेमिटेंस को सांख्यिकीय और मेथोडोलॉजिकल तरीके से कैसे ट्रीट किया जाता है। GATS सेवाओं को सर्विस प्रोवाइडर की राष्ट्रीयता के अनुसार क्लासिफाई करता है। मोड 4 के तहत, एक सर्विस सप्लायर को विदेशी माना जाता है, भले ही वह विदेश में कितने भी समय तक रहे। लेकिन IMF वर्कर्स की सेवाओं को रेजिडेंसी के आधार पर परिभाषित करता है। अगर कोई व्यक्ति एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहता है, तो उसे मेजबान देश का निवासी माना जाता है। निवासियों के बीच लेन-देन को करंट अकाउंट में सेवाओं के एक्सपोर्ट से बाहर रखा जाता है, और इसके बजाय सेकेंडरी इनकम के तहत रिकॉर्ड किया जाता है।

पाकिस्तान में लेबर फोर्स में जुड़ रहे 20 लाख युवा

उन्होंने बताया कि घरेलू स्तर पर नए लेबर फोर्स में शामिल होने वालों को काम देना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के लेबर मार्केट को उसी तरह से बांटा जा सकता है जैसे गुड्स मार्केट को बांटा जाता है। एक इंटरनेशनल और दूसरा घरेलू डिमांड को पूरा करता है। रेमिटेंस से जुड़ी मुख्य चिंताओं को और करीब से देखना फायदेमंद होगा। सबसे पहले, ब्रेन ड्रेन का मुद्दा। पाकिस्तान हर साल अपने लेबर फोर्स में लगभग 20 लाख नए लोगों को जोड़ता है। इनमें से लगभग आधे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 832,000 माइग्रेंट में से केवल 2.6% ही बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं और 5.3% बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं।

पाकिस्तान को खा रही 'डच डिजीज', भारत पैदा कर रहा कंप्यूटर सांइटिस्ट

बेरोजगारी ज्यादा क्यों बढ़ रही है

इस आउटफ्लो के बावजूद बेरोजगारी और अंडरएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रेजुएट बेरोजगारी का अनुमान 23 से 33% के बीच है। अगर लेबर सप्लाई सच में कम हो रही होती, तो रियल सैलरी बढ़नी चाहिए थी। इसके बजाय, पिछले एक दशक के स्टडीज से पता चलता है कि सभी कैटेगरी में रियल सैलरी में गिरावट आई है, जिसमें डिग्री धारकों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। खास बात यह है कि कोविड के दौरान, जब माइग्रेशन धीमा हो गया था, तो रियल सैलरी में बढ़ोतरी देखी गई।

रेमिटेंस का महंगाई पर असर नहीं

हुसैन लिखते हैं कि स्टडीज से पता चलता है कि रेमिटेंस का घरेलू महंगाई पर कोई खास या लगातार असर नहीं होता है। नतीजा काफी हद तक देश की खास आर्थिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। छोटे पैमाने की खेती और पशुपालन में होने वाले फायदे सप्लाई बढ़ा सकते हैं और डिमांड के दबाव को कम कर सकते हैं। जैसे-जैसे परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, बढ़ा हुआ कंजम्पशन मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं मांस, दूध, पोल्ट्री, फल, सब्जियों पर खर्च होता है, न कि इंपोर्ट पर।

पाकिस्तान की खोलकर रख दी पोल

पाकिस्तान में, इंपोर्ट की मांग मुख्य रूप से रेमिटेंस इनफ्लो के बजाय स्ट्रक्चरल और पॉलिसी से जुड़ी दिक्कतों के कारण होती है। इनमें शामिल हैं- डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी पाकिस्तान में उद्योगों को बढ़ावा और सुरक्षा न देने की नीति।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Saturday, 10th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 255 , पृष्ठ 03

नांदेड में चुनावी प्रचार का अनोखा तरीका: सरकारी बॉन्ड पर गारंटी देकर चर्चा में आईं ठाकरे गुट की महिला उम्मीदवार

नांदेड की राजनीति में इन दिनों एक अनोखा चुनावी प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवसेना (ठाकरे गुट) की महिला उम्मीदवार ने अपने प्रचार के दौरान जनता को लुभाने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकारी बॉन्ड पर गारंटी देने की घोषणा की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

उम्मीदवार का कहना है कि अगर वह चुनाव जीतकर आती हैं, तो 100 दिनों के भीतर अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान करेंगी। इनमें सड़क, पानी, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह भी वादा किया है कि अगर वे तय समय में काम पूरा नहीं कर पाईं, तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी।

इस तरह का वादा आमतौर पर चुनावी भाषणों में सुनने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ लोग इसे साहसी और ईमानदार पहल मान रहे हैं, जबकि कुछ मतदाता इसे केवल चुनावी स्टंट बता रहे हैं।

वीडियो में उम्मीदवार खुद इस गारंटी के बारे में विस्तार से बात करती नजर आती हैं। उनका यह अनोखा प्रचार तरीका नांदेड में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना यह होगा कि जनता इस भरोसे को किस तरह स्वीकार करती है।

ELECTION 2026 | Maharashtra Civic Polls Holiday

Maharashtra Civic Polls Holiday: मुंबई, पुणे और 27 अन्य शहरों की सूची देखें, जहां स्कूल, कॉलेज, ऑफिस रहेंगे बंद

मुंबई | मुंबई: महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। जहां नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। एक अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में यह अवकाश रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की व्यवस्था सहित सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है।

राज्य चुनाव आयोग ने दिए जरूरी निर्देश
एक अलग आदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने निर्देश दिया कि पर्याप्त संख्या में मतदान और मतगणनाकर्मियों की नियुक्ति की जाए और सभी संबंधित अधिकारी समय पर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करें।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाघमारे ने यह निर्देश छह और सात जनवरी को आयोजित चुनाव समीक्षा बैठकों के दौरान जारी किए।

29 नगर निगमों की सूची:
मुंबई नगर निगम, ठाणे नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम, उल्हासनगर नगर निगम, कल्याण-डोंबिवली नगर निगम, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम, मीरा-भायंदर नगर निगम, वसई-विरार नगर निगम, पनवेल नगर निगम, नासिक नगर निगम, मालेगांव नगर निगमअहिल्यानगर (अहमदनगर) नगर निगम, जलगांव नगर निगम, धुले नगर निगम, पुणे नगर निगम, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम, सोलापुर नगर निगम, कोल्हापुर नगर निगम, इचलकरंजी नगर निगम, सांगली-मिराज-कुपवाड़ नगर निगम,छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम,नांदेड़-वाघला नगर निगम,परभणी नगर निगम,जालना नगर निगम,लातूर नगर निगम,अमरावती नगर निगम,अकोला नगर निगम,नागपुर नगर निगम,चंद्रपुर नगर निगम

कब समाप्त होगा चुनाव प्रचार?
इन बैठकों में आयोग के सचिव सुरेश काकाणी, पुलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा सभी 29 महानगर पालिकाओं के आयुक्त, पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। काकणी ने कहा कि नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार अवधि 13 जनवरी को शाम 5.30 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या किसी अन्य मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, प्रचार समाप्त होने के बाद सशुल्क प्रिंट विज्ञापनों के लिए कोई पूर्व-प्रमाणन या अनुमति नहीं होगी।

जालना: धार्मिक कार्यक्रम जाते समय सड़क हादसा, पिता-पुत्र की मौत

संवाददाता |

जालना/बदनापूर। धार्मिक कार्यक्रम में जाने के दौरान गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पिता और उसका पुत्र की दुखद मौत हो गई। हादसा राजूर-हसनाबाद फाटा के पास सुंदरवाडी के समीप बुधवार रात करीब साढ़े सात बजे हुआ, जब भरधाव चारचाकी वाहन ने एमएच-20 सीई 9125 नंबर की दुचाकी को जोरदार टक्कर मार दी

बदनापूर निवासी शेख अजीम शेख नसीर (40) और उनके बेटे शेख वसीम (19) को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हुआ, जिसका इलाज जारी है।

मृतक शेख अजीम को स्थानीय जनता में उनके सेवाभावी कार्यों और कब्रिस्तान में निशुल्क कब्र खोदने जैसे कामों के लिए सम्मानित किया जाता था, जिससे समुदाय में उनकी अच्छी पहचान थी। इस दुर्घटना ने बदनापूर शहर में गहरा शोक फैलाया है और लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

राज ठाकरे का आरोप: KDMC चुनाव में 15 करोड़ की पेशकश से उम्मीदवारों को हटाने की कोशिश, भाजपा पर गंभीर निशाना

नाशिक/महाराष्ट्र। आगामी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा-महायुति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज ठाकरे ने दावा किया कि कुछ प्रभागों में कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि की पेशकश कर **कुछ उम्मीदवारों से उनकी उमेदवारी वापस लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पेशकशें और धमकियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए “खतरनाक” और “अस्वीकार्य” हैं।

राज ठाकरे ने नाशिक में एक सभा के दौरान बताया कि कल्याण-डोंबिवली के एक प्रभाग में कुटुंब के तीन उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपये की ऑफर दी गई, जबकि कुछ अन्य को 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपये दिए जाने की भी बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, और बाहरी लोगों को भारी पैसों के दम पर पार्टी टिकट देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।

ठाकरे ने कहा कि यह सब “पैसे के जरिए उम्मीदवारों की खरीद” जैसा है, जिससे वास्तविक जनप्रतिनिधित्व खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर यह भी प्रश्न उठाया कि इतने बड़े पैसों का स्रोत कहां से आता है और क्या यह राजनीतिक प्रक्रिया की मर्यादा को कमजोर नहीं कर रहा है।

राज ठाकरे ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की “भ्रष्ट प्रथाओं” का हिस्सा न बनें और स्थानीय निकायों में वास्तविक नेतृत्व को विजयी बनाने के लिए मतदान करें। उन्होंने कहा कि अगर जनता सचेत रहे तो वह हर चुनौती का सामना कर सकती है।

नागपुर: चार बच्चों वाली उम्मीदवार की मनपा चुनाव में उमेदवारी वैध कैसे? छानबीन पर सवाल

नागपुर। आगामी नागपुर महानगरपालिका (मनपा) 2026 के चुनाव में एक विवादास्पद मामला सामने आया है। चार बच्चों वाली उम्मीदवार पुष्पा मुकेश वाघमारे का नामांकन वैध स्वीकार किया गया, जबकि नियम के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति अयोग्य होते हैं।

उम्मीदवार ने अपने हलफनामे में स्पष्ट लिखा कि उनके चार बच्चे हैं, जिनमें से दो का जन्म 12 सितंबर 2001 के बाद हुआ। यह नियम के खिलाफ है, लेकिन छानबीन के दौरान उल्लंघन पकड़ा नहीं गया और उनका नामांकन स्वीकृत कर दिया गया।

विशेष कारण यह था कि हलफनामा 2 जनवरी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

मनपा अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देता है, तो मामला वहीं तय होगा। प्रशासनिक लापरवाही और नियम उल्लंघन पर राजनीतिक दल और नागरिकों ने तीव्र आलोचना की है, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

संक्रांति पर मतदाताओं को उपहार देना होगी भारी, PMC आयुक्त का चेतावनी

पुणे – आगामी पुणे नगर निगम (PMC) चुनाव के मद्देनजर आयुक्त नवल किशोर राम ने उम्मीदवारों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को उपहार या वसूल सामग्री बांटना पूरी तरह से निषिद्ध है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

प्रशासन ने अब तक आचार संहिता के उल्लंघन में कई मामलों में संपत्ति जब्त और प्राथमिकी दर्ज की है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि संक्रांति के त्योहार के दौरान भी कोई उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उपहार नहीं बांटेगा, वरना कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।

इस चेतावनी का मकसद चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।

पवार परिवार में पिघलने लगी विवाद की बर्फ, इस दिन हो सकता है एनसीपी के विलय का ऐलान, जानें सबकुछ

मुंबई | मुंबई: शरद पवार और अजित पवार के बीच विवाद की बर्फ पिघलने लगी है। महानगरपालिका चुनाव के बाद 22 जनवरी को दोनों एनसीपी के विलय की संभावना है। शुक्रवार को अजित पवार ने स्वीकार किया कि पवार परिवार के अंदर अब सभी तरह के विवाद खत्म हो गए हैं। परिवार में तनाव खत्म हो गए हैं और जल्द ही एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो सकते हैं। दूसरा कारण अजित पवार ने यह बताया कि दोनों दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की यहीं मांग कर रहे है इसलिए तो हम लोग पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव गठबंधन कर लड़ रहे हैं।

सुप्रिया सुले ने क्या कहा?
इधर, शरद पवार की बेटी व लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर ही पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के चुनाव में एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आए।

जब उनसे मोदी सरकार में उनके केंद्र मंत्री बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताकर टाल दिया।

दो साल पहले एनसीपी के हो गए दो टुकड़े
शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गठन किया था। दो साल पहले ही एनसीपी के दो टुकड़े हो गए। एक का अध्यक्ष शरद पवार और दूसरे का अध्यक्ष उनके भतीजे अजित पवार बने। अजित पवार एनडीए में शामिल होकर सत्ता में आ गए। उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। आगे चलकर अजित पवार ने एनसीपी का नाम और 'घड़ी' चिन्ह भी अपना लिया, जबकि शरद पवार के गुट को नया नाम, एनसीपी (शरदचंद्र पवार), और नया चिन्ह, तुरही मिला। अब पार्टी ने विलय की बात हो रही है।

दबाव डालकर पार्टी बदलने को किया जा रहा है मजबूर
शुक्रवार को अजित पवार ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपने सिद्धांतों को त्याग दिया है। अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। अब दल बदलना बहुत आम हो गया है, जिसमें नेताओं को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी विचारधाराओं को लगभग त्याग दिया है। नेता जहां चाहें वहां जा रहे हैं और जो चाहें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को प्रलोभन देकर अपने पाले में लाया जा रहा है, जबकि अन्य पर उनके खिलाफ लंबित जांचों का डर दिखाकर और यह आश्वासन देकर दबाव डाला जा रहा है कि उनके दल बदलने के बाद जांच एजेंसियों से निपट लिया जाएगा।

अजित पवार ने क्या कहा?
अजित पवार ने दावा किया कि अब राजनीति में खुलेआम धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पवार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बार-बार दल-बदलने के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि जिनके पास पैसा और बाहुबल है, वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग जातिगत मुद्दों को उठाकर वोट हासिल करने की सोच रहे हैं, वे यही रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार का मूल्यांकन उसकी चुनावी योग्यता के आधार पर किया जा रहा है, न कि एक नेता के रूप में उसके कार्यों के आधार पर। एक नया चलन सामने आया है जहां उम्मीदवारों की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है।

अकोट में बीजेपी नेताओं की AIMIM से दोस्ती से हाईकमान के होश उड़े, BMC चुनाव में पंगे का डर

मुंबई: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए अलग-अलग स्थानों पर एआईएमआईएम और कांग्रेस का समर्थन लिया है। इन मामलों के सामने आने से केंद्रीय नेतृत्व भी हैरान है। पार्टी को डर है कि ऐसे प्रयोगों का असर आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और अन्य बड़े नगर निगमों के चुनावों में उसकी राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है। इसी वजह से अब राज्य स्तर पर भी अनुशासनात्मक रुख अपनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, दो नगर परिषदों से जुड़े मामले सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, जिसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एक मामले में बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के साथ मिलकर नगर परिषद बनाई थी, जबकि दूसरे मामले में कांग्रेस के सहयोग से सत्ता संतुलन साधा गया।

अकोट में क्यों किया AIMIM से गठबंधन
बता दें कि अकोट में हुए हालिया नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की ने मेयर पद जीत लिया था। इसके बावजूद 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी को सिर्फ 11 ही सीटें मिली थी। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने यहां एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। इस गठबंधन को ‘अकोट विकास मंच’ नाम दिया गया। इस चुनाव में 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी AIMIM में इस गठबंधन का हिस्सा बन गई। शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हैं। यहीं नहीं इस नए गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करा दिया गया है।

अंबरनाथ में कांग्रेस पार्षदों का सहारा
एक अन्य विवादास्पद मामले में अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के 12 पार्षदों का समर्थन लिया। कांग्रेस ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए इन पार्षदों को निलंबित कर दिया और स्थानीय ब्लॉक इकाई को भंग कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने राजनीतिक संतुलन अपने पक्ष में करने के लिए सभी 12 कांग्रेस पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस गठबंधन में एनसीपी और कुछ निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी के साथ रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अंबरनाथ के इन 12 पार्षदों को अयोग्य घोषित कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुने जाने के बाद दल बदलना संविधान और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी दल के प्रतीक पर जीत हासिल करने के बाद स्वतंत्र समूह बनाना या दूसरी पार्टी में शामिल होना गंभीर उल्लंघन है, जिसे चुनौती दी जाएगी।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Saturday, 10th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 255 , पृष्ठ 04

NWMC ELECTION 2026 | सरकारी जमीन के घर नियमित, इनामी जमीन पर मालिकाना हक

सरकारी जमीन पर बने घर होंगे नियमित, इनामी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने के लिए कानून में बदलाव – चंद्रशेखर बावनकुळे

नांदेड : नांदेड महानगरपालिका की होने वाली चुनाव केवल उम्मीदवारों और नेताओं के भविष्य का फैसला नहीं करेगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जनकल्याणकारी योजनाओं को शहर में प्रभावी ढंग से लागू करने का माध्यम बनेगी। यह बात राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि सरकारी और महानगरपालिका की जमीनों पर बने सभी घरों को नियमित किया जाएगा तथा पात्र नागरिकों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे।

प्रभाग क्रमांक 5 में भाजपा उम्मीदवार साहेबराव गायकवाड, शांभवी साले, जयश्री पावडे और एडवोकेट महेश कनकदंडे के प्रचार हेतु अशोकनगर में आयोजित जनसभा में मंत्री बावनकुळे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नांदेड शहर की मदतमास और खिदमतमास जैसी इनामी जमीनों पर रहने वाले नागरिकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। चुनाव के बाद वे स्वयं नांदेड आकर सरकारी जमीनों

पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाए बिना नहीं रुकेंगे, ऐसी गारंटी भी उन्होंने दी।

इस अवसर पर सांसद अशोकराव चव्हाण, सांसद अजित गोपछडे, पूर्व मंत्री डी. पी. सावंत, विधायक किशनराव वानखेडे, विधायक श्रीजया चव्हाण, विधायक जितेश अंतापूरकर, जिला अध्यक्ष संतुक हंबर्डे सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री बावनकुळे ने कहा कि सांसद अशोकराव चव्हाण के नेतृत्व में नांदेड शहर का उल्लेखनीय विकास हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत का संकल्प लिया है, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विकसित महाराष्ट्र का विजन है। इसी के अनुरूप नांदेड को भी विकसित शहर बनाने के लिए महानगरपालिका में भाजपा की सत्ता आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के बाद महापौर और सभी नगरसेवक मिलकर शहर का सर्वसमावेशक विकास आराखड़ा तैयार करेंगे। यह आराखड़ा सांसद अशोकराव चव्हाण के माध्यम से तीन महीने के भीतर सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद विकास कार्यों के लिए भरपूर निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

सभा में यह भी कहा गया कि भाजपा की सत्ता आने पर बुनियादी सुविधाओं, आवास, सड़क, पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। नांदेड को एक आधुनिक, समृद्ध और समावेशी शहर बनाने का संकल्प भाजपा नेतृत्व ने इस जनसभा के माध्यम से दोहराया।

हदगांव शहर का विकास पारदर्शिता और ईमानदारी से किया जाएगा : नगराध्यक्षा रोहिणी वानखेडे

हदगांव।
हदगांव नगरपालिका का पदग्रहण समारोह आज (दि. 8) को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नगराध्यक्षा पद की शपथ लेने के बाद नागरिकों को संबोधित करते हुए नगराध्यक्षा रोहिणी भास्कर वानखेडे ने कहा कि उनके कार्यकाल में शहर के सभी विकास कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खुला प्रवर्ग महिला से पहली बार रोहिणी वानखेडे नगराध्यक्षा बनी हैं।

इस अवसर पर शिवसेना के विधायक हेमंत पाटील, पूर्व सांसद सुभाष वानखेडे, विधायक बाबुराव कदम कोहळीकर, विधायक किशनराव वानखेडे (उमरखेड), विभिन्न धार्मिक स्थलों के महंत, बौद्ध समाज के धर्मगुरु, शहर की सभी मस्जिदों के मौलाना सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। साथ ही शिवसेना व भाजपा के जिला प्रमुख, नगरसेवक और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

नगराध्यक्षा वानखेडे ने कहा कि शहरवासियों को शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, प्रत्येक वार्ड में आंगनवाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएंगी। गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए आंगनवाड़ियों को सशक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हदगांव शहर के समग्र विकास के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर विकास आराखड़ा तैयार किया जाएगा और आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

"हिंद की चादर" कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का सहयोग जरूरी – जिलाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड, 9 जनवरी (स्रोत -जिमाका,नांदेड़) : नांदेड शहर में 24 एवं 25 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले भव्य "हिंद की चादर" कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का सक्रिय सहयोग और योगदान आवश्यक है। यह विचार जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

कार्यक्रम की तैयारियों के संदर्भ में जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने आज जिले की विभिन्न सामाजिक संगठनों, उद्यमियों, होमगार्ड समदेशकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आयोजन को सफल बनाने में प्रशासन का साथ देने की अपील की।

इस अवसर पर निवासी उपजिलाधिकारी किरण अंबेकर, तहसीलदार संजय वारकड, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, जिले के उद्यमी, होमगार्ड समदेशक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिलाधिकारी कर्डिले ने कहा कि सभी संबंधित विभागों और संगठनों के समन्वय से ही इतना बड़ा कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सकता है।

कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के तहत दो समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक सुबह 11 बजे संपन्न हुई, जिसमें स्कूल बस चालक संघ, होमगार्ड समदेशक, उद्यमी और विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल हुए। इसके पश्चात होटल एसोसिएशन, व्यापारी संघ और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता से दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

दोनों बैठकों में "हिंद की चादर" कार्यक्रम के आयोजन, व्यवस्थापन, प्रचार-प्रसार, आपसी समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए और कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया। उपस्थित संगठनों ने कार्यक्रम के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने के संकेत, अभिभावक रखें दस्तावेज तैयार

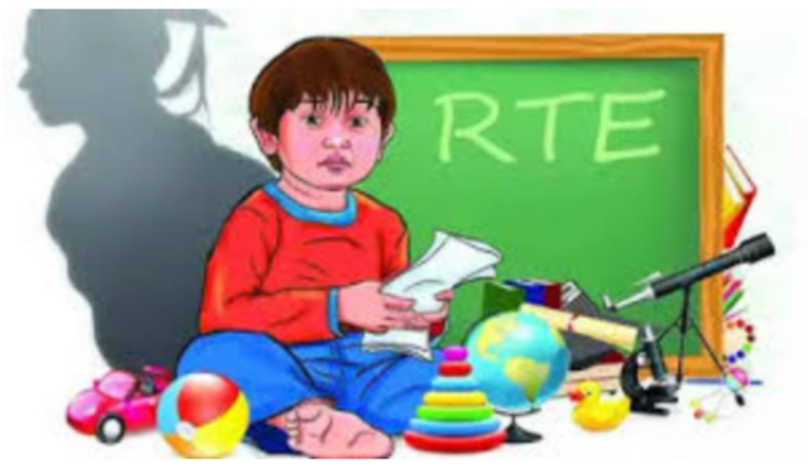

संवाददाता |

नांदेड : निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जनवरी के अंत तक या फरवरी माह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इसका विस्तृत समय-सारिणी शीघ्र घोषित की जा सकती है।

पिछले वर्ष तकनीकी खामियों और प्रशासनिक कारणों से प्रवेश प्रक्रिया में काफी विलंब हुआ था, लेकिन इस बार विभाग ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।

दिन-ब-दिन बढ़ती शिक्षा लागत और निजी स्कूलों की भारी फीस के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावकों के लिए आरटीई योजना काफी सहायक साबित हो रही है। आरटीई के तहत चयनित छात्रों की स्कूल फीस और अन्य शैक्षणिक खर्च में बड़ी राहत मिलती है।

आरटीई प्रवेश के लिए पात्र निजी स्कूलों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की जाएगी। स्कूलों की सूची, उपलब्ध सीटें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें वंचित और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहती हैं।

प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए शिक्षा विभाग पोर्टल सुधार, स्कूल सत्यापन, आवेदन जांच और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।

राशन वालों को ही आयुष्मान? जरूरतमंद परिवार परेशान

नांदेड : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान मानी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और दस्तावेजी बाधाओं के कारण अनेक पात्र नागरिक योजना के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं।

शिकायतें सामने आ रही हैं कि केवल उन्हीं परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके नाम राशन कार्ड सूची में दर्ज हैं। जबकि कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जिनके पास वैध राशन कार्ड नहीं है या जिनके कार्ड में त्रुटियां हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पा रहा है। ई-सेवा केंद्रों पर आवेदन के दौरान राशन कार्ड को अनिवार्य किए जाने से समस्या और बढ़ गई है।

कई मामलों में वैध राशन कार्ड होने के बावजूद डाटाबेस में नाम नहीं मिलना, जानकारी लिंक न होना या ऑनलाइन प्रक्रिया अटक जाना आम बात हो गई है। सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए आवाहन किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में प्रशासन से मांग की जा रही है कि जटिल शर्तों को शिथिल कर वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय में 13 जनवरी को पेंशन अदालत का आयोजन

(स्रोत -जिमाका,नांदेड़) |

Indergarh- नांदेड, 9 जनवरी — नांदेड जिले के राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिल्हाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। यह पेंशन अदालत जनवरी माह के दूसरे मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड में आयोजित की जाएगी।

इस पेंशन अदालत के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि सहित अन्य लंबित प्रकरणों पर सुनवाई कर उनका त्वरित निवारण किया जाएगा। जिन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत है, वे पेंशन अदालत के दिन स्वयं उपस्थित रहकर अपनी लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। जिल्हाधिकारी नांदेड ने जिले के सभी पात्र सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर न्याय और सुविधा प्रदान करना है।

आयुष्मान भारत व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण बना नांदेड का शासकीय मेडिकल कॉलेज

(स्रोत -जिमाका,नांदेड़)

नांदेड, 9 जनवरी।
डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं रुग्णालय, विष्णुपुरी (नांदेड) ने आयुष्मान भारत योजना तथा उससे संलग्न महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जनस्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। गरीब, जरूरतमंद और सामान्य वर्ग के मरीजों को गंभीर एवं अतिगंभीर बीमारियों पर पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराकर अस्पताल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख के सक्षम नेतृत्व तथा योजना की अध्यक्ष एवं उप-अधिष्ठाता डॉ. शीतल राठोड-चव्हाण के मार्गदर्शन में अस्पताल ने वर्ष 2025 के दौरान 7041 से अधिक मरीजों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया। इस अवधि में शासन से लगभग 18 करोड़ 85 लाख 47 हजार 800 रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई, जिससे जांच, दवाइयों एवं जटिल शल्यक्रियाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

अस्थिरोग विभाग में हिप व नी रिप्लेसमेंट तथा रीढ़ की जटिल शल्यक्रियाएं, औषधि विभाग में जीबीएस, ब्रेन हेमरेज व हार्ट अटैक जैसे गंभीर मामलों का सफल उपचार किया गया। शल्यचिकित्सा विभाग ने कैंसर सहित पेट व आंतों की जटिल सर्जरी, जबकि स्त्रीरोग विभाग ने गर्भाशय कैंसर व लेप्रोस्कोपिक शल्यक्रियाएं सफलतापूर्वक कीं।
बालरोग विभाग द्वारा नवजात एवं गंभीर बाल मरीजों को जीवनदान दिया गया। ईएनटी, नेत्ररोग, श्वसनरोग, त्वचा, मनोरोग, दंत शल्यचिकित्सा सहित सभी विभागों ने समन्वय के साथ उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। जटिल शल्यक्रियाओं में बधिरीकरण (एनेस्थीसिया) विभाग की भूमिका भी सराहनीय रही।
रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विभागों द्वारा आवश्यक जांचें की गईं तथा औषध विभाग के माध्यम से सभी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। नर्सिंग स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों के सतत परिश्रम से यह सफलता संभव हुई।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सीमित संसाधनों के बावजूद मानवबल का योग्य नियोजन कर जनसामान्य तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है।

हिंद की चादर" जनजागृति अभियान : सचखंड पब्लिक स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित

नांदेड, 9 जनवरी (स्रोत -जिमाका,नांदेड़) — श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम "हिंद की चादर" के सफल आयोजन एवं व्यापक जनभागीदारी के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से व्यापक जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नांदेड स्थित सचखंड पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए विशेष जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम 24 व 25 जनवरी 2026 को नांदेड में आयोजित किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों तक इस ऐतिहासिक आयोजन का संदेश पहुँचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को माध्यम बनाया जा रहा है। सचखंड पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को "हिंद की चादर" कार्यक्रम के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भारत का मानचित्र साकार किया तथा "हिंद की चादर" गीत का सामूहिक गायन कर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, शाळेच्या प्राचार्य अनिल कौर, चत्तर सिंग टंक, रणदीप सिंग पिरंगे, करणपाल सिंग लोणी वाले, भगेंद्र सिंह फौजी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले ने विद्यार्थियों से संवाद साधते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान केवल एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था। "हिंद की चादर" कार्यक्रम इसी संदेश को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम है।

उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से अपील की कि वे प्रभात फेरी, भाषण प्रतियोगिता, निबंध, चित्रकला, रंगोली जैसे विविध उपक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय सहभाग लें। विद्यार्थियों में इतिहास और राष्ट्र के प्रति जागरूकता निर्माण करने की दिशा में यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सचखंड पब्लिक स्कूल की प्राचार्या अनिल कौर खालसा के मार्गदर्शन में विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। साथ ही गुरुबचन सिंह शिलेदार, प्राचार्य आईटीआई खालसा का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति, त्याग और सामाजिक एकता का संदेश प्रभावी रूप से पहुँचा।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)